समक्ष आर.एन मित्तल , माननीय न्यायमूर्ति।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य– याचिकाकर्ताओं

बनाम

वी. के. खन्ना और अन्य, – प्रतिवादियों

1984 का सिविल रिवीजन संख्या 765

21 मार्च, 1984

सिविल प्रक्रिया संहिता (***1908*** का ***5)*** **-** धारा ***80*** और आदेश ***39*** नियम ***1*** और ***2*** वादी द्वारा धारा ***80*** द्वारा प्रदान किए गए नोटिस के बिना दायर किया गया मुकदमा - वादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन भी दायर किया गया - ऐसे आवेदन को बयानों पर निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया प्रतिवादी के वकील का-वाद-पत्र-क्या धारा ***80*** के तहत नोटिस देने के बाद प्रस्तुति के लिए वापस किया जाना चाहिए।

अभिनिर्णित **,** सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ***80*** की उपधारा (***1)*** के मद्देनजर सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी सरकार या सार्वजनिक

अधिकारी को दो महीने का नोटिस न दिया गया हो। उप-धारा (***2)*** उक्त नियम के लिए एक अपवाद बनाती है और यह अदालत को अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति को उप-धारा (***1)*** के तहत कोई नोटिस दिए बिना मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकती है, यदि उसे पता चलता है कि मुकदमा किस प्रयोजन के लिए है सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करना। हालाँकि, अदालत उप-धारा के तहत तब तक राहत नहीं दे सकती जब तक कि सरकार या सार्वजनिक अधिकारी को मांगी गई राहत के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। प्रावधान में कहा गया है कि यदि न्यायालय की राय है कि कोई तत्काल या तत्काल राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो उसे उपधारा (***1)*** की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद प्रस्तुति के लिए वादपत्र वापस कर देना चाहिए। धारा में संशोधन ***1976*** में सरकार या सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ नोटिस दिए बिना तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए एक उपाय प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था क्योंकि संशोधन से पहले किसी व्यक्ति को ऐसी राहत की आवश्यकता होने पर कोई उपाय नहीं था। उपधारा (***2)*** के प्रावधान अनिवार्य हैं। इसलिए, जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादी को आदेश ***39,*** नियम ***1*** और ***2*** के तहत दावा की गई राहत नहीं दी जा सकती है, तो यह उस

पर इस निर्देश के साथ वादी को वापस करने के लिए बाध्य होगा कि इसे आवश्यकतानुसार नोटिस देने के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संहिता की धारा ***80*** की उपधारा ***(1)***।

(पैरा 6 और 7)

श्री बी.सी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के न्यायालय के दिनांक 25 जनवरी, 1984 के आदेश, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6 से 10 और 12 के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, में धारा 115, सी.पी.सी. के तहत संशोधन।

अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए.के. मित्तल, अधिवक्ता, के साथ याचिकाकर्ता।

जे.एस. चहल, वकील, नंबर 1 के लिए, दीपक थापर, वकील, नंबर 1 के लिए नंबर 9।

निर्णय

आर.एन.मित्तल , माननीय न्यायमूर्ति।

(1) यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के 25 जनवरी, 1984 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब कैडर का सदस्य है। उन्हें मार्च, 1982 में पंजाब सरकार के आयुक्त और सचिव के रूप में चंडीगढ़ में तैनात किया गया था और तब से वह लगातार वहीं तैनात हैं। वह रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा है। 2,000 प्रति माह. यह आरोप लगाया गया है कि वह सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन पूल) आवंटन नियम, 1972 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के तहत टाइप IV घर का हकदार है। नियमों के तहत प्रतिवादी संख्या 2 की अध्यक्षता में एक आवास आवंटन समिति (उच्च) का गठन किया गया है और इसमें उक्त प्रतिवादी के अलावा प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक शामिल हैं। समिति तीसरी से आठवीं श्रेणी के मकान आवंटित करती है। आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 2 नियमों की अनदेखी कर आउट-ऑफ-टर्न आधार पर मकानों का आवंटन कर रहा था.इसके बाद, याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने पुलिस के समक्ष एक पूरक बयान दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि उसकी मृत बेटी ने दहेज के आरोपों के संबंध में उसे गुमराह किया था। उसने उसे बताया था कि उसका पति शुरू से ही उसे मारना चाहता था। उन्होंने आगे कहा कि सरनाम सिंह, श्रीमती। कमलेश, श्रीमती कोमल और सोनू (प्रतिवादी संख्या 2 से 5) की गीता की मौत में कोई भूमिका

नहीं थी। जांच के बाद चालान पेश किया गया और पति और उसके दो दोस्तों को आरोपी बनाया गया। उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को कॉलम संख्या 2 में रखा गया था।

(3) सेक्टर 5, चंडीगढ़ में मकान नंबर 57 (जो टाइप IV का घर है) को श्री ओ. पी. मल्होत्रा, मुख्य अभियंता, चंडीगढ़ द्वारा खाली कर दिया गया था। इसे श्री एम. सी. गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, प्रतिवादी संख्या 11 को आउट-ऑफ-टर्न आवंटित किया गया था, हालांकि वह घर के हकदार नहीं थे। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी नंबर 2 को मनमाने तरीके से तदर्थ आधार पर सरकारी आवासों का समय से पहले आवंटन करने से रोका जाए और प्रतिवादी नंबर 1 से 10 को सेक्टर 5 में मकान नंबर 57 का कब्जा सौंपने से श्री गुप्ता को रोका जाए।

(4) मुकदमे के साथ-साथ वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद इसे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रतिवादियों संख्या 1 से 10 और 12 को घर का कब्जा सौंपने से रोका जाए। , प्रतिवादी संख्या 11 को और प्रतिवादी संख्या 11 को मुकदमे का निर्णय होने तक उक्त मकान पर कब्जा करने से रोका जाए। न्यायालय ने 21 नवंबर, 1983 को प्रतिवादी संख्या 1 से 10 और 12 को आवेदन का नोटिस जारी किया और प्रतिवादी संख्या

11 के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की और उसे अगले आदेश तक घर पर कब्जा करने से रोक दिया। 21 नवंबर, 1983 को सरकारी वकील ने अदालत में कुछ बयान दिया जिसके कारण उक्त आवेदन निरर्थक हो गया और खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादियों की ओर से एक आवेदन दायर किया गया कि वादी की ओर से विज्ञापन के लिए आवेदन दिया गया था। -प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा खारिज कर दी गई थी, इसलिए संहिता की धारा 80 की उप-धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद वादपत्र को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाए। आवेदन का वादी ने विरोध किया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी थी कि अदालत ने धारा 80 के तहत नोटिस की सेवा से छूट दे दी है और इस स्तर पर मामले को फिर से नहीं उठाया जा सकता है। अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया, -आक्षेपित आदेश के तहत। तीन प्रतिवादी इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए इस न्यायालय में आये हैं।

(5) निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या धारा 80 की उपधारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद वादपत्र को वादी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना चाहिए। प्रश्न में उपधारा (1) की व्याख्या शामिल है और (2) संहिता की धारा 80, जो इस प्रकार है:-

“80 (1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी कृत्य के संबंध में सरकार (जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार सहित) या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसे सार्वजनिक अधिकारी द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता में किया गया कार्य, जब तक कि लिखित नोटिस उसके कार्यालय में पहुंचा दिए जाने या छोड़ दिए जाने के अगले दो महीने की समाप्ति न हो जाए।

(2) ऐसे सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में सरकार (जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार सहित) या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ तत्काल या तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, न्यायालय की अनुमति से, उपधारा (1) के अनुसार कोई नोटिस तामील किए बिना; लेकिन अदालत मुकदमे में, चाहे अंतरिम हो या अन्यथा, राहत नहीं देगी, सिवाय इसके कि सरकार या सार्वजनिक अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, मुकदमे में मांगी गई राहत के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर दिया जाए;

बशर्ते कि न्यायालय, यदि पक्षों को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मुकदमे में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, तो उपधारा (1) की आवश्यकताओं का

अनुपालन करने के बाद वादपत्र को प्रस्तुत करने के लिए उसे वापस कर देगा।

(6) उप-धारा (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी सरकार या सार्वजनिक अधिकारी को दो महीने का नोटिस नहीं दिया गया हो। उप-धारा (2) एक अपवाद बनाती है उक्त नियम और यह अदालत को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के तहत कोई नोटिस दिए बिना मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है, यदि उसे पता चलता है कि मुकदमा सरकार या जनता के खिलाफ तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से है। अधिकारी. हालाँकि, न्यायालय उप-धारा के तहत तब तक राहत नहीं दे सकता जब तक कि सरकार या सार्वजनिक अधिकारी को मांगी गई राहत के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता। प्रावधान में कहा गया है कि यदि न्यायालय की राय है कि कोई तत्काल या तत्काल राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो उसे उप-धारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद प्रस्तुति के लिए वादपत्र वापस कर देना चाहिए। धारा में संशोधन 1976 में सरकार या सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ नोटिस दिए बिना तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए एक उपाय प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था क्योंकि संशोधन से पहले किसी व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता होने पर कोई उपाय नहीं मिल पाता था। राहत। उपधारा (2) के प्रावधान अनिवार्य हैं।

उपर्युक्त दृष्टिकोण में मैं त्रिपुरा राज्य में गौहाटी उच्च न्यायालय और अन्य बनाम सजल कांति सेनगुप्ता (1) की टिप्पणियों से दृढ़ हूं, जिसमें यह देखा गया था। : ■–

"इन प्रावधानों में स्पष्ट आदेश यह है कि यदि वादी को तत्काल या तत्काल राहत दी जानी है तो सी.पी.सी. की धारा 80 की उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। वर्तमान में इससे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन यदि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुकदमे में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, तो उपधारा (1) की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए वादपत्र वापस कर दिया जाएगा। इसलिए, यह पाया गया है कि अत्यावश्यक या तत्काल राहत के मामले में भी अंतरिम या अन्यथा न्यायालय दूसरे पक्ष को मुकदमे में प्रार्थना की गई राहत के संबंध में कारण बताने का अवसर देने से छूट नहीं दे सकता है। प्रावधान अनिवार्य है और इसे तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक राहत की तात्कालिकता/तत्कालता, अंतरिम या अन्यथा, प्रावधानों के तहत पर्याप्त रूप से निपटाई जाती है।'

(7) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी को उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा दावा की गई राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए,

यह उस पर निर्भर था कि वह वाद-पत्र को परंतुक के तहत वादी को इस निर्देश के साथ लौटा दे कि इसे उप-धारा (1) के अनुसार नोटिस देने के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, ट्रायल कोर्ट ने धारा 80 की उपधारा (2) की सही व्याख्या नहीं की है। नतीजतन, मैं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करता हूं और उसे निर्देश देता हूं कि वह संहिता की धारा 80 की उपधारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद वादी को वादपत्र वापस कर दे ताकि उसे प्रस्तुत किया जा सके। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
नूँह, हरियाणा